मणिपुर में तिपाईमुख परियोजना का भारी विरोध जनसुनवाई नहीं हो सकी

उत्तर–पूर्वी राज्य मणिपुर में प्रस्तावित तिपाईमुख पनबिजली परियोजना के लिए 26 मार्च 2008 को प्रस्तावित जनसुनवाई स्थानीय लोगों के भारी विरोध के कारण नहीं हो सकी। जनसुनवाई का प्रभावित होने वाले लोगों एवं विभिन्न स्थानीय संगठनों ने जमकर विरोध किया। तुईवाई और बराक नदी के संगम पर प्रस्तावित इस परियोजना की प्रस्तावित क्षमता 1500 मेगावाट है। परियोजना के लिए राज्य के तमेंगलांग जिले के केईमाई में यह पहली जनसुनवाई प्रस्तावित थी। प्रभावित इलाकों में कार्यरत संगठन सिटीजन कंसर्न फॉर डैम्स एंड डेवलेपमेंट (सीसीडीडी), ऐक्शन कमेटी अगेंस्ट तिपाईमुख डैम (एसीटीआईपी) एवं कमेटी अगेंस्ट तिपाईमुख डैम (सीएटीडी) ने जनसुनवाई का जमकर विरोध किया।

सीसीडीडी के संयुक्त सचिव जितेन युमन ने बताया कि 26 मार्च की जनसुनवाई की आयोजक मणिपुर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) एवं नॉर्थ इस्ट इलेक्ट्रिक पॉवर कारपोरेशन (नीपको) ने जनसुनवाई में प्रभावित इलाके के सिर्फ एक खास समुदाय की राय लेने की कोशिश की। इस तरह सरकार लोगों के बीच आपसी सम्बन्ध को बिगाड़ना चाहती है। सीएटीडी के संयोजक अराम पामेई के अनुसार इस जनसुनवाई को लोगों को परियोजना के बारे में शिक्षित करने के मंच में तब्दील कर दिया गया। उन्होंने बताया कि परियोजना के खिलाफ इस विरोध अभियान की शुरूआत विभिन्न स्थानीय संगठनों के साथ संयुक्त रूप से 25 मार्च को आयोजित एक जनसुनवाई के माध्यम से हुई। जेलियांगरोग स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर और नुंगबा एरिया विलेज अथॉरिटी एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस जनसुनवाई में 30 प्रभावित गांवो के लोगों ने हिस्सा लिया था। लोगों ने दावा किया कि प्रभावित इलाकों में भूमि, नदी, जंगल पहाड़ आदि लोगों की आजीविका, संस्कृति, पहचान एवं परंपरा के अभिन्न अंग हैं और इनसे दूर हो जाने से बहुत लोगों का जीवन अत्यंत संकटग्रस्त हो जाएगा। स्थानीय लोगों ने मणिपुर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव को पहले ही लिखित ज्ञापन दिया था कि 26 मार्च की प्रस्तावित जनसुनवाई का रद्द किया जाय क्योंकि यह आवश्यक कानूनी प्रावधानों को पूरा नहीं करती है।

जनसुनवाई के लिए सरकार ने काफी संख्या में सीमा सुरक्षा सुरक्षा बल के जवानों की व्यवस्था कर रखी थी। जनसुनवाई के लिए उपस्थित विभिन्न अधिकारियों के सामने लोगों द्वारा उठाये गये विभिन्न सवालों का जवाब न मिलने के कारण सायं 6 बजे तक जनसुनवाई शुरू नहीं हो सकी। अंत में सीमा सुरक्षा बल के कमांडेंट ने लोगों को लिख कर दिया कि लोगों के विरोध के कारण जनसुनवाई आयोजित नहीं की जा सकी।

एसीटीआईपी का कहना है कि जब स्थानीय लोगों द्वारा जनसुनवाई को नकार दिया गया तो फिर सरकार को इस परियोजना पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि क्षेत्र के लोग परियोजना निर्माण का कभी समर्थन नहीं करेंगे। उन्होंने मांग की कि परियोजना के लिए नीपको (NEEPCO) एवं राज्य सरकार के बीच हुए समझौते को रद्द किया जाय। साथ ही यह भी मांग की कि जब तक स्थानीय लोगों को उनकी भूमि एवं अन्य संसाधनों पर अधिकार को पूरी तरह मान्यता नहीं मिल जाती तब तक सरकार को राज्य में कोई बड़ी परियोजना नहीं लगानी चाहिए।

ऐक्शन कमेटी अगेंस्ट तिपाईमुख प्रोजेक्ट (एसीटीआईपी) द्वारा जारी रिपोर्ट का हिन्दी अनुवाद